खुदरा व्यापार में विदेशी दैत्यों को न्योता

अमरीकी साम्राज्य एक ऐसा दैत्य है जो पिछले 25 सालों से हमारे देश में कहर ढा रहा है। इसे आमंत्रित करने वाले हमारे देश के धूर्त और कायर शासक रोज-ब-रोज इस दैत्य के आगे आम जनता की बली चढ़ा रहे हैं। पिछले दिनों जनता के विरोध को अनदेखा करते हुए सरकार ने 4 करोड़ से ज़्यादा खुदरा व्यापारियों की जिंदगी को इस दैत्य की भेंट चढ़ाने का फैसला लिया। संसद में इस दौरान पक्ष-विपक्ष की पार्टियों में हुई नूरा-कुश्ती भी पूरे देश ने देखी जिसमें यह बात और भी ज़्यादा पुख्ता हो गयी कि सभी पार्टियों में बस नाम का अंतर रह गया है। सभी पार्टियां दिलो-जान से दैत्य कि सेवा में लगी हुई हैं।

आज वालमार्ट, मेंट, मेट्रो, टेस्को, केयरफोर जैसी दैत्यकार कम्पनियां अपने भारतीय सहयोगियों-भरती, टाटा, बिडला, रिलांइस इत्यादि के साथ मिलकर खुदरा व्यापार में घुस चुकी हैं। वालमार्ट इस क्षेत्र की सबसे विराट अमरीकी कम्पनी है। पिछले दिनों अमरीकी सिनेट में इस बात का खुलासा हुआ था कि इस कम्पनी ने भारत में अपने पक्ष में माहौल बनाने पर 125 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। वालमार्ट चहती थी कि अमरीकी सरकार खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश को खोलने के लिये भारत सरकार की बांह मरोड़े। वालमार्ट छोटे व्यापारियों को उजाड़ने, अपने कामगारों को बेहद कम वेतन देने, श्रम कानूनों का खुलेआम उल्लंघन करने और उत्पादकों से कम कीमत पर माल खरीदने के लिये पूरी दुनिया में बदनाम है। कम वेतन पर ज्यादा काम लेने कि धूर्ततापूर्ण चालों से परेशान वालमार्ट के मज़दूर आंदोलन छेड़े हुए हैं। इसकी तबाही मचाने वाली कारगुजारियों से आजीज आये अमीरीकी इसे ''वेन्टोविले का दानव'' कहते हैं। यह कम्पनी अमरीकी साम्राज्यवाद का दर्पण है जिसमें सकल घरेलू उत्पाद बढ़ने के बावजूद जनता की जिंदगी लगातार बदतर होती जा रही हैं। खुदरा क्षेत्र में उतरी बाकी कम्पनियों की दास्तां भी वालमार्ट से अलग नहीं है।

भारत का कुल खुदरा व्यापार लगभग 21,75,00 करोड़ है। इससे लगभग 4 करोड़ परिवारों का भरण-पोषण होता है। इसमें संगठित व्यापार जैसे-मॉल, सुपर बाजार, मेगामार्ट केन्द्रीय भंडार, बड़े-बड़े शो-रूम आदि का हिस्सा केवल 5 प्रतिशत है। बाकी 95 प्रतिशत हिस्सा किराना दुकानदार, खोखा, ठेला-खोमचा, फड़, हाट बाजार, मेला और फेरीवालों का है। इसी विशाल बाजार पर देशी-विदेशी दैत्यो की नजर गड़ी है। वालमार्ट का कुल कारोबार भारत के कुल खुदरा व्यापार से थोड़ा ही कम है। जबकि यह महज 15 लाख लोगों को ही रोज़गार देता है। कोई भी अनुमान लगा सकता है कि खुदरा व्यापार में आने वाली ये कंपनियां करोड़ों लोगों की रोजी-रोटी छीन लेंगी। ऐसे में इन कम्पनियों के आने से करोड़ों नये रोज़गार पैदा होने का सरकारी दावा अपने परिवार का पेट पाल रहे 4 करोड़ लोगों के खिलाफ क्रूर मजाक है।

खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश से किसानों को होने वाले फायदे गिनवाते हुए सरकार का कहना है कि इससे बिचौलिए खत्म हो जायेंगे और किसान को फसल का ज़्यादा दाम मिलेगा। लेकिन यह तो कोई भी समझ सकता है कि देशी खुदरा व्यापार में घुसने के लिये लाखों रुपये की लॉबिग कर सात समन्दर लांघ कर आने को बेचैन ये दैत्य कितनी भलमनसाहत से बिचौलियों के हटने से होने वाले मुनाफे को किसान की झोली में डालेंगे। वैसे वालमार्ट तय कर चुकी है कि वह किसानों से सीधे फसल नहीं खरीदेगी। क्योंकि भारत में किसानी बहुत छोटी और बिखरी हुई है।

सीधे किसानों से फसल खरीदने के लिये उसे श्रमिक यातायात और भण्डारण के मद में ज्यादा खर्च उठाना होगा, जिसमें उसका मुनाफा कम होगा। इसके लिए वह स्थानीय कंपनियों से समझौते कर रही है। ये सप्लायर छोटे-मोटे बिचौलियों को बाहर धकेल कर खुद ही बिचौलिए बन बैठेंगे। ये सप्लायर कम्पनियां छोटे व्यापारी और उनकी मंडियों को तबाह कर अपना एकाधिकार कायम करने के लिए दो-चार साल तक तो किसानों को थोड़े अधिक दाम दे सकती हैं। लेकिन ऐसा होने के बाद किसान सिर्फ उन्ही कम्पनियों को अपना माल बेचने पर मजबूर हो जायेंगे। इन्हीं कम्पनियों के इशारों पर सरकार फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले ही खत्म कर चुकी है। इस स्थिति में ये कम्पनियां बेलगाम होकर तबाही मचाने को आजाद होंगी।

दूसरा महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि कम्पनियां 70 प्रतिशत माल विदेशों से खरीदने को आजाद हैं। बाकी 30 प्रतिशत माल भी वे बड़े उत्पादकों से ही खरीदेंगी। वाशिंगटन आम सहमति के चलते अमरीकी निर्देशों पर अमल करते हुए सरकार पहले ही किसानों को दी जाने वाली सबसिडी को काफी कम कर चुकी है, जबकि खुद अमरीका और यूरोप में किसानों को हजारों गुना सबसिडी दी जा रही है। जाहिर है कि हमारे किसान वहां के किसानों से मुकाबला नहीं कर पायेंगे। उनकी फसल ज्यादा सस्ती होगी और खुदरा व्यापार में लगी कम्पनियां उन्हीं से अपना माल खरीदेंगी।

देश का किसान पहले ही संकटग्रस्त है। 40 प्रतिशत किसान खेती छोड़ना चाहते हैं। और हर रोज औसतन 40 से ज़्यादा किसान आत्महत्या करने को विवश हैं अमरीकी और यूरोपीय साम्राज्यवादी दानव अपने संकटों को लगातार तीसरी दुनिया पर थोपते जा रहे हैं। ऐसे में ये विदेशी दानव खेतों को शमशान में बदल देंगे। यह तय है। खुदरा व्यापार में विदेशी निवेश की इजाजत एक तरफ तो आम जानता को कंगाली के नरककुंड में झोंक देगा, वहीं दूसरी ओर यह मुट्ठीभर सरमायेदारों के लिये नयी सम्भावनाएं भी लेकर आया है। देशी पूंजीपति इन विदेशी कम्पनियों से गठजोड़ करके क्षेत्र में भरपूर मुनाफा बटोरेंगे। बड़े-बड़े बिल्डर, मंदी के भय जिनकी से नींद हराम है, इन कंपनियों के लिये जमीन उपलब्ध कराने तथा गोदाम और स्टोर बनाने में अपना उज्वल भविष्य देख रहे हैंनिजी शिक्षण संस्थाएं तो पहले से ही खुदरा मैनेजमेंट के पाठ्यक्रम शुरू हो चुकी हैं और अब करोड़ों की कमाई की बाट देख रही हैं। राजनेता पहले ही अरबों की घूस खा चुके हैं। अभिनेता, मॉडल और क्रिकेट खिलाड़ी इन कंपनियों के विज्ञापन के लिये लालायित हैं।

व्यापार के लिये आयी ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने 200 साल तक भारत को गुलाम बनाया था। जयचंदों और मीरजाफरों की वंशज हमारी सरकारें पहले ही सैकड़ों कम्पनियों से दुरभिसंधी कर उन्हें देश में घुसकर लूट की खुली छूट दे चुकी हैं। नयी आर्थिक नीतियों के नाम पर देश को नयी गुलामी की जंजीरों में पकड़ा जा चुका है। यह नयी अर्थिक गुलामी साफ-साफ दिखायी नहीं देती, लेकिन यह पहले की प्रत्यक्ष गुलामी से भी ज़्यादा कष्टप्रद और क्रूर है। पिछले 20-25 सालों के हालात से इस नयी गुलामी को समझा जा सकता है। आज देशी-विदेशी लुटेरे सरमायेदारों की एकता मजबूत है। लेकिन मेहनतकश जनता का संगठित संघर्ष उनका मुकाबला कर सकता है।

-देश विदेश

व्यवसाय के लिये पढ़ाई न करें : राज्यपाल की मुफ्त सलाह

फ़रीदाबाद (म. मो.) दिनांक 3 मार्च को सुधा रस्तोगी डेंटल कॉलेज के दीक्षांत समारोह में भाषण देते हुए हरियाणा के राज्यपाल जगन्नाथ पहाड़िया ने सब से महत्वपूर्ण बात छात्रों को यह बताई कि वे नौकरी अथवा व्यवसाय पाने के लिये पढ़ाई न करें। पढ़ लिख कर उन्हें समाज सेवा की ओर भी ध्यान देना चाहिये।

विदित हो कि उक्त कॉलेज राज्य के बिक्री कर विभाग से सेवानिवृत एक बड़े अधिकारी द्वारा व्यवसाय के तौर पर चलाया जा रहा है। उस अधिकारी ने सब से पहले पानीपत के निकट भारी रकम लगा कर एक इन्जीनीयरिंग कॉलेज खोला था। उसमें भारी मुनाफ़ा देख कर एक अन्य व उक्त कॉलेज खोला। इस कॉलेज में बी डी एस तक की पढ़ाई के लिये छात्रों से 30-40 लाख तथा एम डी एस के लिये 40 से 50 लाख तक की वसूली की जाती है। इस पढ़ाई को करने के बाद बमुश्किल 15-20 प्रतिशत छात्र ही कोई ढंग की नौकरी प्राप्त कर पाते हैं। यद्यपि देश की जरूरतों को देखते हुए बड़ी संख्या में दंत-चिकित्सकों की आवश्यकता है, परन्तु सरकार इन्हें काम पर लगा कर जनता की जरूरतों को पूरा नहीं करना चाहती, लिहाजा दंत चिकित्सकों की अनेकों पोस्ट खाली पड़ी हैं।

दूसरी बात यह भी गौरतलब है कि जो छात्र इतनी बड़ी रकम खर्च करके डॉक्टर बनेगा तो वह येन प्रकारेण इसे शीघ्रातिशीघ्र ब्याज सहित वसूल करने का प्रयास भी करेगा; जाहिर है वसूली भी जनता से ही होनी है। दूसरी ओर अकेले उस शिक्षा व्यवसायी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता जो इस धंधे में भारी पूंजी लगा कर मोटा मुनाफ़ा कमा रहा है। इसके लिये पूर्णतया सरकार, जिसका एक अंग खुद राज्यपाल भी है, दोषी है। राष्ट्रनिर्माण के लिये अति आवश्यक शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्य को भी जो सरकार व्यापारियों को सौंप दे वह कैसे जनहितैषी हो सकती है ? कहने की जरूरत नहीं कि शिक्षा व्यापारियों द्वारा कमाये जाने वाले मुनाफ़े में से एक हिस्सा बाकायदा कुर्सीनशीन राजनीतिज्ञों व अफ़सरों तक भी किसी न किसी रूप में पहुंचता है। इस सब के बावजूद पहाड़िया डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों को उपदेश देते हैं कि पढाई पूरी करने के बाद नौकरी पाने की कोशिश न करें। नौकरी न करें तो क्या करें ? नौकरी पाने के लिये यूं भी आजकल पढ़ाई व योग्यता की कोई खास जरूरत रह नहीं गयी है। जैसे तैसे झूठी-सच्ची डिग्री का जुगाड़ करके राजनेताओं की सेवा पानी करो और नौकरी पाओ का सिद्धान्त काफ़ी प्रचलित एवं सफ़ल है। मेहनत से पढ़ाई करके योग्यता प्राप्त करने वालों को आज कोई पूछता नहीं है। ऐसे में पहाड़िया का प्रवचन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

नम्बर वन हरियाणा मनरेगा की लूट में भी

गत सप्ताह प्रमुख अखबारों के प्रथम पृष्ठ पर सबसे ऊपर छपा था 'मनरेगा में भी नम्बर वन हरियाणा।' इसमें बताया गया है कि राज्य में सर्वाधिक मज़दूरी दर 214 रुपया प्रति दिन दी गयी। देश के अन्य किसी भी राज्य में इससे अधिक दर पर मज़दूरी नहीं दी गयी। अब कोई पूछे इस मुख्य मन्त्री महोदय से कि इसमें नम्बर वन की कौन सी बात है ? राज्य के किसी भी भाग में कोई भी मज़दूर 300 रुपया प्रतिदिन से कम पर काम करने को उपलब्ध नहीं है। हैरानगी की बात तो यह है कि इनकी सरकार को 214 रुपया दिहाड़ी पर कोई मज़दूर मिल कैसे गया ? दरअसल मिल इसलिये गये कि मनरेगा अपने आप में एक राष्ट्रीय स्तर का घोटाला है। इस योजना में काम करने के पैसे नहीं मिलते बल्कि काग़जों में खानापूर्ति करके रुपये बांटे जाते हैं। रकम का बड़ा हिस्सा सरकारी अफ़सर व छोटे मोटे नेता डकार जाते हैं तथा कुछ हिस्सा अपने उन लग्गुए भग्गुओं को बांट देते हैं। जो काग़जों पर चुपचाप आ कर दस्तखत कर देते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अरबों खरबों रुपये खर्च होने के बावजूद इस योजना के अन्तर्गत बनी कोई महत्वपूर्ण नहर, रेलवे लाइन, सड़क, पुल, इमारत, बांध आदि नज़र नहीं आता। इसके तहत किये गये कामों के नाम पर बस मिट्टी खोद कर इधर से उधर डाली बताई जाती है, जिसका कोई पुख्ता हिसाब किताब न हो कर सब फ़जीवाड़ा होता है। रोज़गार प्रदान करने के नाम पर एक ओर तो इस पाखंड पर अरबों रूपया स्वाहा किया जा रहा है दूसरी ओर सरकार के ही हर विभाग में लाखों रिक्तियां बरसों से किसी काम करने वाले की बाट जोह रही हैं। देश भर के स्कूलों में 12 लाख से अधिक शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, रेलवे में लाखों पद खाली पड़े हैं, अस्पतालों में डाक्टरों व अन्य स्टाफ़ की कमी से जनता परेशानी भुगत रही है। अकेले इसी नम्बर वन हरियाणा में जिसे मुख्य मन्त्री हुड्डा शिक्षा का हब बताते हैं, कम से कम 30000 स्कूली व 5000 कॉलेज शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं। सरकारी रोड़वेज की हज़ारों बसें ड्राइवरों कंडक्टरों व वर्कशाप स्टाफ की कमी के चलते खाली खड़ी जंग खा रही हैं। जिन कार्यकुशल एवं प्रशिक्षित कामगारों को काम की जरूरत है तथा विभागों एवं प्रतिष्ठानों को उनकी जरूरत है, उन्हें काम पर रखने को तो सरकार के पास पैसा नहीं है जबकि मनरेगा जैसे पाखंड पर जनता के पैसे को पूरी बेदर्दी के साथ बर्बाद किया जा रहा है। बेशर्मी की इन्तहा तब और बढ़ जाती है जब इस बर्बादी को भी अपनी उपलब्धि बताने के लिये लाखों रुपये के विज्ञापन छपवाये जाते हैं। न जाने किस जन्म की दुश्मनी यह सरकार देश की जनता से निकाल रही है ?

पेज 1 का शेष भाग

लड़ाई : भ्रटाचार से अन्ना की, काले धन से बाबा की, राजनीतिज्ञों से केजरीवाल की

अन्ना के पास लोकपाल के बाद सिवाय भ्रष्ट राजनीतिज्ञों को कोसने और जनता के लामबंद होने की अपीलें ही होती हैं। वे कहते जाते हैं, लोग सुनते जाते हैं, व्यवस्था पूर्ववत चलती रहती है।

बाबा रामदेव की काले धन से महज एक आयामी लड़ाई है उनका एकमात्र आयाम है कि स्विस बैंकों एवं अन्य विदेशी पूंजी स्वर्गों में जमा काला धन वापस भारत में लाया जाय। वे बीच-बीच में इटली का नाम भी इस संदर्भ में लेते हैं ताकि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जो मूल रूप से इतालवी हैं, को निशाने पर रखा जा सके।

स्वंय एक व्यवसायी होने के नाते रामदेव को यह अच्छी तरह पता होगा कि कैसे किसी भी व्यवसाय में काला धन पैदा होता है, फलता-फूलता है और कैसे उसका निवेश पुन: अर्थव्यवस्था में किया जाता है। वे यह भी जानते ही होंगे कि उनके प्रवचनों को सुनने वाले ज़्यादातर अनुयायी किसी न किसी रूप में काले धन की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दे रहे हैं। यह भी किसी से छिपा नहीं है कि काला धन पैदा करने का सबसे बड़ा स्रोत है जायदाद का करोबार। इस धंधे में हर कदम पर काला धन पैदा होता है, शायद हर हफ़्ते इतना कि जितना तमाम विदेशी बैंकों में भी न हो। अगला चैनल जिसके माध्यम से जम कर टैक्स चोरी की जाती है, वह है विदेश-व्यापार। इसके जरिये मॉरिशस जैसे टैक्स स्वर्ग बने देशों में फ़र्जी कम्पनी मुख्यालय दिखा कर भारतीय बाज़ारों से होने वाला सारा मुनाफ़ा बिना टैक्स दिये ही हजम कर लिया जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था को मुनाफ़ाखोर पूंजी के माध्यम से मनमाफ़िक डगमगाने वाला तीसरा क्षेत्र है सीधे विदेशी निवेश का। यह निवेश शेयर बाजारों एवं रिटेल बाज़रों में घुसकर अपना जलवा दिखाने को स्वतंत्र है।

बाबा रामदेव काले धन के इन तीनों महा-स्रोतों पर मुंह बंद रखते हैं। वजह न वे बताते हैं, और न उनसे कोई पूछता है। जानना मुश्किल नहीं है कि काले धन के खिलाफ़ उनकी लड़ाई कितनी एकतरफ़ा है। इससे आम जनता को कोई राहत नहीं मिलेगी क्योंकि उसकी मेहनत दी कमाई की क्रय शक्ति तो तब तक घटती ही जायेगी जब तक कि देश में हो रहे तमाम कारोबारों में रोज़ाना काला धन पैदा होता व खपता रहेगा।

राजनीतिज्ञों के विरोध में खड़े अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों का आलम यह है कि वे भी उसी तर्ज पर राजनीति करने में जुटे हैं, वादे, वादे, सिर्फ़ वादे। तर्क वही कि जनता ने पुरानी दुकानें तो देख ली अब हमारा सौदा भी तो देख लो। उनका सौदा क्या है ? इस बारे में वे सिर्फ़ इतना कहते प्रतीत होते हैं कि दूसरे चोर हैं और हम ईमानदारी से काम करेंगे। केजरीवाल के साथ-साथ एक प्रमुख सहयोगी हैं प्रशान्तभूषण। वे और उनके पिता शान्तिभूषण मशहूर वकील हैं और मानवाधिकार चैम्पियन के रूप में स्वंय को पेश करते हैं। इन बाप-बेटे की अपनी घोषित सम्पत्ति लगभग 250 करोड़ रुपया है। भारत में अपनी मेहनत की कमाई से और पूरा टैक्स दे कर इतना पैसा क्या कोई जोड़ सकता है ?

बाबा रामदेव और अरविंद केजरीवाल की पृष्ठभूमि कहीं न कहीं संघ परिवार से जुड़ती है। अन्ना हजारे के एकमात्र सक्रिय एवं विश्वस्त सहयोगी के रूप में बचे हैं पूर्व सेनाध्यक्ष वी के सिंह। भ्रष्टाचार के तले दबी जनता और कब तक इन पर भरोसा करे ? और क्यों ?

-त्रिनेत्र